

मंत्रिमण्डल के माध्यम से नागरिकता की शिक्षा

गुरुराजराव के

आवाज़ें

स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसका मूल उद्देश्य, अपनी सभी नियोजित और व्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिकता-शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम-सहगामी गतिविधियाँ भी शामिल हैं। मैं इमालपुर में अपने स्कूल के अनुभव साझा कर रहा हूँ, यह स्कूल कुछ अनूठे तरीकों से नागरिकता-शिक्षा प्रदान करने में सफल रहा है।

हमारा प्रयोग

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इमालपुर (ज़िला यादगीर) में कक्षा 1 से 7 वीं तक के करीब 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह कर्नाटक के सीमावर्ती स्कूलों में से एक है, जहाँ अधिकांश विद्यार्थियों की मातृभाषा तेलुगू है। 2012 से 2015 तक, मैंने प्रधान शिक्षकों के लिए गठित स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम (SLDP) के साथ काम किया। कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, प्रत्येक प्रधान शिक्षक को अपने स्कूल में एक परियोजना का चुनाव कर, इस पर स्कूल में सभी हितधारकों को साथ लेकर काम करना था। उन्हें इस अनुभव से सीख भी लेनी थी।

बसप्पा स्कूल में प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में 20 साल और प्रधान शिक्षक के रूप में 8 साल कार्य करने का अनुभव था। उनकी परियोजना थी - एक मंत्रिमण्डल के गठन और कार्यान्वयन के माध्यम से स्कूल में एक लोकतांत्रिक परिवेश बनाना। ब्लॉक के अन्य सभी प्रधान शिक्षकों की तुलना में यह एक अनूठी पहल थी क्योंकि यह संवैधानिक मूल्यों और नागरिकता-शिक्षा को बढ़ावा देने से सम्बन्धित थी। उस स्कूल में इस पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका था और प्रधान शिक्षक SLDP कार्यक्रम के माध्यम से इसे जारी रखना चाहते थे।

मजबूत मंत्रिमण्डल के गठन को लेकर प्रधान शिक्षक व अन्य शिक्षकों ने सभी बच्चों के साथ विस्तृत बैठक की। उन्होंने बच्चों को भरोसा दिलाया कि मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वहन और निर्णय लेने के लिए उन्हें एक स्वतंत्र और भयरहित वातावरण प्रदान करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह मंत्रिमण्डल ही स्कूल की प्रक्रियाओं को चलाएगा और इसके पास स्कूल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लागू करने का अधिकार होगा। इसमें विद्यार्थियों को सवाल पूछने,

राय व्यक्त करने और स्कूल की सभी प्रक्रियाओं में बराबर के भागीदार बनने के अधिकार शामिल थे।

नामांकन और वोटों के साथ उचित ढंग से चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री एवं शिक्षा, संस्कृति, स्वच्छता, पर्यावरण, वित्त मंत्री और अन्य सदस्यों के साथ मंत्रिमण्डल का गठन किया गया। सभी सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराया गया। जल्दी ही, निर्वाचित सदस्यों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू कर दिया। बसप्पा और वेंकटेश (सहायक अध्यापक) ने विद्यार्थियों की भूमिकाओं से सम्बन्धित शंकाओं को दूर करते हुए उनकी मदद की। बच्चों को अपनी भूमिकाओं को बेहतर समझने में लगभग छह महीने लग गए। पर तब तक इसका असर स्कूल में दिखने लगा था। बच्चों ने अपने शिक्षकों से सवाल करना शुरू कर दिया था। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

- स्कूल देर से आने वाले शिक्षकों से बच्चों ने सवाल करना शुरू कर दिया।
- उन्होंने स्कूल में संसाधनों की कमी के बारे में प्रधान शिक्षक को आधिकारिक शिकायत की। उदाहरण के लिए, चॉक, डस्टर, पीने के पानी के बर्तन और शिक्षकों के लिए सामग्री की कमी।
- कई बार याद दिलाने के बाद भी स्कूल परिसर में कक्षाओं और पीने के पानी के बर्तन की सफ़ाई नहीं करने के लिए सुबह की सभा में स्कूल परिचारक से जवाब माँगा गया।
- बच्चों को कठोर दण्ड देने वाले (या मारने वाले) या किसी भी तरह से अपमानित करने वाले शिक्षकों को भी चिन्हित किया गया।

बच्चों ने स्कूल में वास्तविक लोकतंत्र का आनन्द लेना शुरू कर दिया। मासिक बैठकें की जाती थीं जिसमें सभी निर्वाचित सदस्य मिलते और स्कूल के मुद्दों और किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करते। प्रधान शिक्षक के मुताबिक बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और शिक्षकों और बड़ों के सामने खुद को अभिव्यक्त करने का डर कम हुआ। विद्यार्थियों का व्यवहार कई मायनों में बेहतर हुआ; वे नियमित रूप से स्कूल आने लगे, कार्य पूरा करने लगे, कक्षा में ध्यान देते हुए सक्रिय रूप से भाग लेने लगे।



हितकारी परिणाम

मंत्रिमण्डल के सदस्य बनने की माँग हर साल बढ़ती गई। अनुभवी विद्यार्थियों ने जूनियर सदस्यों को अपनी भूमिका निभाने के लिए साथ जोड़ना करना शुरू कर दिया। सवाल करना, बच्चों में विकसित होने वाली प्रमुख क्षमता थी। वे स्कूल में हर बात पर सवाल करने लगे। इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपने काम में ज्यादा जवाबदेह और समय के पाबन्द हो गए। इस वजह से, स्कूल ने आस-पास के क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की। शिक्षकों, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP) और आस-पास के स्कूलों के बच्चों ने विद्यार्थियों के बढ़े हुए आत्मविश्वास और स्कूल के सभी निर्णय ले रहे मंत्रिमण्डल को देखने के लिए स्कूल का दौरा करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा तीन वर्षों में किए गए कार्यों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

- पाठ्यपुस्तकों की कमी थी और बच्चे इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रधान शिक्षक से लगातार शिकायत कर रहे थे। एक दिन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP), जो पाठ्यपुस्तक वितरण के लिए जिम्मेदार थे, अपने नियमित कार्य के सन्दर्भ में विद्यालय आए। बच्चे उनके चारों ओर खड़े हो गए और उनसे सवाल करने लगे। उन्होंने बच्चों से वादा किया कि वह इस मुद्दे को सुलझाएँगे और तीन दिनों के भीतर ही सभी बच्चों को उनकी पाठ्यपुस्तकें मिल गईं। वह ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बाद में इस घटना को विभिन्न शिक्षक-प्रशिक्षण प्लेटफार्मों पर साझा करते और शिक्षकों को अपने स्कूलों में इस तरह की पहल करने के लिए प्रेरित करते ।

- विद्यालय में केवल एक शौचालय था जो सभी 200 बच्चों के उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं था। लड़कियाँ अवकाश के दौरान अपने घर शौचालय का इस्तेमाल करने जातीं और लड़के स्कूल के बाहर, खुले में शौच के लिए जाते थे। मंत्रिमण्डल ने प्रधान शिक्षक के समक्ष इस मुद्दे को उठाया और स्कूल की टीम ने स्थानीय ग्राम-पंचायत से स्कूल विकास एवं निगरानी समिति (SDMC) के साथ मिलकर बच्चों के लिए शौचालय बनाने का अनुरोध किया। तीन माह बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थियों ने शान्तिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाया और ग्राम-पंचायत के बाहर एकत्रित होकर स्कूल में शौचालय निर्माण की माँग की। दस दिन के भीतर ही अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई और छह माह के भीतर नए शौचालयों का निर्माण करवा दिया गया।
- एक अन्य घटना में, बच्चे, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) को यह समझाने में सफल रहे कि कैसे परिसर की सफाई के लिए नियुक्त अस्थायी स्कूल अटेंडेंट ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और प्रधान शिक्षक को धमकाया। इसके चलते लापरवाही करने वाले अटेंडेंट के खिलाफ कार्यवाही की गई। बच्चों द्वारा स्थिति को सही ढंग से, आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी पूर्वाग्रह के समझाते देख BEO बच्चों से प्रभावित हुए।

मंत्रिमण्डल के माध्यम से स्कूल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करने के लिए शुरू की गई इस पहल का विद्यार्थियों

पर काफ़ी असर पड़ा। वे सवाल करने, भेदभाव के खिलाफ़ आवाज़ उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम थे। इससे उन्हें सही और ग़लत को बेहतर आँकने और अपने कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूक होने में भी मदद मिली।

इसी तरह बच्चे नागरिकता के बारे में सीखते हैं और समाज के बेहतर नागरिक बनते हैं। हो सकता है कुछ स्कूल इस तरह

से काम कर भी रहे हों, लेकिन सभी स्कूलों में हमें इसी तरह लोकतंत्र का अभ्यास करने की ज़रूरत है। यदि बच्चे अपने स्कूलों, घरों और गाँवों में मुद्दों से जूझने के लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करना सीख जाते हैं, तो वे बड़े होकर लोकतंत्र का सम्मान करेंगे और सक्रिय नागरिक बनेंगे। यह स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के निरन्तर व नियमित प्रयासों से हासिल किया जा सकता है।



गुरुराजराव के अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन, ज़िला संस्थान, मांड्या, कर्नाटक में रिसोर्स पर्सन हैं। उन्हें शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शैक्षिक पदाधिकारियों के साथ काम करने का समृद्ध अनुभव है। उनके अधिकांश प्रयास शिक्षण-अभ्यासों में बदलाव लाने और सरकारी स्कूलों में बच्चों के अधिगम को बेहतर बनाने पर केन्द्रित हैं। उनसे gururajrao.k@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** सात्विका ओहरी

नागरिकता से सम्बद्ध शिक्षा की विषयवस्तु और लक्ष्य क्या हों? यह कोई सादा-सरल सवाल नहीं है। इसका जवाब कई तरह से दिया जा सकता है। अलग-अलग सम्भव दृष्टिकोणों के बीच गम्भीर असहमतियाँ भी हो सकती हैं। और यह सवाल खतरनाक भी है। लेकिन अगर स्कूलों और शिक्षकों को अपने समयकाल में प्रासंगिक रहना है और अपने विद्यार्थियों को कुछ सार्थक, अर्थपूर्ण शिक्षा देनी है, तो उन्हें यह सवाल उठाना ही होगा।

- अमन मदान, नागरिकता की विभिन्न संस्कृतियाँ : किसका शिक्षण हो?, पेज 1